an>

Title: Need to provide funds under Additional Central Assistance for Left Wing Extremism Affected Districts in Bihar particularly in Aurangabad Parliamentary Constituency, Bihar.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) ः देश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित विभिन्न प्रांतों के करीब 82 जिलों में भारत सरकार के द्वारा विकास की योजना समेकित कार्य योजना (आई.ए.पी.) चलायी गयी थी जिसका नाम बदलकर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) किया गया है। इन योजना के माध्यम से बिहार के 11 जिले, जिसमें हमारे संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया जिले भी शामिल हैं, पूर्व में इस प्रयोजन हेतु विकास कार्य के लिए प्रति वर्ष 30 करोड़ रूपए आवंटित होते थे।

यद्यपि समेकित कार्य योजना/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के तहत विकास की योजनाओं के चयन हेतु गठित समिति में किसी भी जनप्रतिनिधि सांसद/विधायक को शामिल नहीं किया गया है अर्थात् उनके सुझाव पर पूर्व में कुछ कार्य होते थे जिसके कारण विकास के कार्य होते थे जिससे पिछड़े और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की किरणें पहुँचाकर नक्सल समस्या का नियंत्रण अथवा समाधान में बड़ी भूमिका निभायी जा सकती है। वर्तमान में समेकित कार्य योजना/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना में विकास हेतु राशि का आवंटन बंद है जिससे विकास की नई योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो रही हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि समेकित काय योजना/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना को पुनः प्रारम्भ किया जाए ताकि नक्सली क्षेत्रों के विकास के लिए संबंधित जिलों को धन भेजा जा सके।